

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 27-12-2024

विषय सूची

क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत का पहला स्नातक (UG) माइनर प्रोग्राम चंम्ह

बैड लोन (Bad Loans) में कमी

ब्रिटेन की संसद ने सहायता प्राप्त मृत्यु/असिस्टेड डाइंग (Assisted Dying) को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया

वैश्विक पोलियो पुनरुत्थान और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

भारत का समुद्री क्षेत्र

स्कूल में सीखने के परिणामों को बेहतर बना सकता है

संक्षिप्त समाचार

मलेरिया उन्मूलन में भारत की प्रगति

डॉ. मनमोहन सिंह का योगदान

बाल्ड ईगल (Bald Eagle)

वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक सक्षमीकरण के लिए समिति

चीन विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध बनाएगा

सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती

ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन

क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत का पहला स्नातक (UG) माइनर प्रोग्राम

समाचार में

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत का प्रथम स्नातक (UG) माइनर प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के साथ साझेदारी की है।

प्रोग्राम का परिचय

- इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्वांटम क्रांति के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करना है, जिससे देश क्वांटम नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हो सके।
- यह सभी इंजीनियरिंग विषयों के छात्रों के लिए खुला है।
- **फोकस:**
 - क्वांटम कम्प्यूटेशन और सिमुलेशन
 - क्वांटम संचार और क्रिप्टोग्राफी
 - क्वांटम सेंसिंग
 - क्वांटम सामग्री और उपकरण
 - इसे शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए बनाया गया है।
- **पाठ्यक्रम संरचना:** कार्यक्रम में एक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम है जो छात्रों को उनके तीसरे सेमेस्टर से प्रारंभ होने वाले 30 में से 18 क्रेडिट चुनने की अनुमति देता है।
 - यह परियोजना-आधारित सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, अंतःविषय प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी

- यह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर निर्भर करता है, जो उप-परमाणु कणों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें 1920 के दशक में नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग और एर्विन श्रोडिंगर जैसे भौतिकविदों द्वारा विकसित किया गया था।
- क्वांटम तकनीक नई नहीं है और यह परमाणु ऊर्जा एवं फोन जैसे उपकरणों में अर्धचालक जैसे क्षेत्रों में मौलिक रही है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग

- क्वांटम कम्प्यूटिंग अत्याधुनिक कम्प्यूटर विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी के अद्वितीय गुणों का उपयोग करके सबसे शक्तिशाली शास्त्रीय कम्प्यूटरों की क्षमता से परे समस्याओं को हल करता है।
- इसमें क्वांटम हार्डवेयर (सूचना को संसाधित करने वाली भौतिक प्रणालियाँ) और क्वांटम एल्गोरिदम (समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ) दोनों शामिल हैं।
- क्वांटम कम्प्यूटर क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित हैं, जिसे 1982 में रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तावित किया था।
- **आधारभूत सिद्धांत:** पारंपरिक कम्प्यूटर गणना के लिए बिट्स (0 या 1) का उपयोग करते हैं।
 - क्वांटम कम्प्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं, जो 0, 1 या दोनों अवस्थाओं में एक साथ (सुपरपोजिशन) उपस्थित हो सकते हैं।
 - क्यूबिट इनटेंग्लमेंट हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक क्यूबिट की स्थिति दूसरे की स्थिति को तुरंत प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि दूरी पर भी।

संभावना

- क्वांटम कंप्यूटर अत्यधिक जटिल समस्याओं को पारंपरिक सुपरकंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से हल कर सकते हैं, जिससे गणना का समय हजारों वर्षों से घटकर मिनटों में आ सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा को मौलिक रूप से अलग-अलग तरीकों से संसाधित कर सकती है, जिससे प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति:

- शोर के एल्गोरिथ्म (1994) ने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर बड़ी संख्याओं को शीघ्रता से गुणन कर सकते हैं, जिससे डेटा सुरक्षा प्रभावित होती है।
 - IBM का क्यू सिस्टम वन (2019) पहला सर्किट-आधारित वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर था।
 - गूगल के साइकैमोर प्रोसेसर (2019) ने क्वांटम वर्चस्व प्राप्त किया, क्लासिकल सुपरकंप्यूटर की तुलना में समस्याओं को तीव्रता से हल किया।
 - गूगल की विलो चिप (2023) त्रुटि-सुधारित गणना कर सकती है, जो बेहतर स्केलेबिलिटी दिखाती है।

वर्तमान सीमाएँ:

- क्वांटम कंप्यूटर बनाना व्ययकारी और जटिल है।
- त्रुटि दर और डिकोहेरेंस के कारण क्यूबिट स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
- दवा खोज और खगोल विज्ञान जैसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए लाखों क्यूबिट की आवश्यकता होती है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 में आठ वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रारंभ किया गया था।
 - इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना और उनकी क्षमता का लाभ उठाना है।

निष्कर्ष

- क्वांटम कंप्यूटिंग में परिवर्तनकारी क्षमता है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों पर नियंत्रण पाना होगा।
- इस तकनीक में भारत का निवेश भविष्य के नवाचार और विकास के लिए इसके महत्व को दर्शाता है।

Source :TH

बैड लोन(Bad Loans) में कमी

संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPAs) का अनुपात 13 वर्षों से अधिक समय में सबसे कम हो गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) में, देश में वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट मजबूत बनी रही, जो ऋण और जमा दोनों में निरंतर विस्तार द्वारा चिह्नित थी।
- **NPA अनुपात में गिरावट:**
 - **मार्च 2010-11:** बैंकों का सकल NPA 2.35% था।

- **मार्च 2024:** बैंकों के GNPA_s में वर्ष-दर-वर्ष 15.9% की कमी आई।
- **सितंबर 2024:** सकल NPA अनुपात में सुधार हुआ और यह 2.5% हो गया।
- **क्षेत्रवार:**
 - सितंबर 2024 के अंत में कृषि क्षेत्र के लिए GNPA_s अनुपात 6.2% पर सबसे अधिक और खुदरा ऋण के लिए 1.2% पर सबसे कम रहा।
 - सितंबर 2024 के अंत में शिक्षा ऋण का GNPA_s अनुपात 2.7% गिर गया।
 - यह खुदरा ऋण खंडों में सबसे अधिक रहा, इसके बाद क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ और उपभोक्ता सतत वस्तुएँ हैं।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात

- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात एक वित्तीय मीट्रिक है जिसका उपयोग किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिसमें उसकी कुल ऋण परिसंपत्तियों के उस अनुपात को मापा जाता है, जिसे गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) ऐसे ऋण या अग्रिम हैं, जिन पर उधारकर्ता ने ब्याज या मूलधन का भुगतान करना बंद कर दिया है।
- **उच्च GNPA अनुपात:** यह डिफॉल्ट के जोखिम वाले ऋणों के उच्च अनुपात को इंगित करता है, जो बैंक के लिए वित्तीय संकट का संकेत हो सकता है।
 - इससे पता चलता है कि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो का एक बड़ा भाग अपेक्षा के अनुरूप आय उत्पन्न नहीं कर रहा है।
- **निम्न GNPA अनुपात:** यह बैंक के लिए बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है, तथा डिफॉल्ट के जोखिम वाले ऋणों की संख्या कम होती है।
- **नियामक पहलू:** बैंकों को वित्तीय पारदर्शिता और जोखिम मूल्यांकन उपायों के भाग के रूप में अपने GNPA अनुपातों की नियमित रूप से नियामकों को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

गैर - निष्पादित ऋण

- बैड लोन (Bad Loan), जिन्हें गैर-निष्पादित ऋण (NPLs) के रूप में भी जाना जाता है, वे ऋण होते हैं, जिनमें उधारकर्ता एक विस्तारित अवधि, सामान्यतः 90 दिन या उससे अधिक, के लिए आवश्यक भुगतान (ब्याज या मूलधन) करने में विफल रहता है।
- ये ऋण उधारदाताओं के लिए जोखिमपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से चुका पाना संभव नहीं होता, जिससे वित्तीय हानि होती है।

बैड लोन (Bad Loan) के कारण

- **खराब ऋण देने की प्रथाएँ:** बैंक और वित्तीय संस्थान कभी-कभी उचित ऋण मूल्यांकन या उचित परिश्रम के बिना उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं।
- **आर्थिक मंदी:** आर्थिक मंदी और उद्योग-विशिष्ट संकट उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
- **कॉर्पोरेट कुप्रबंधन:** खराब प्रबंधन या अकुशल संचालन वाली कंपनियाँ प्रायः लाभ कमाने और ऋण चुकाने के लिए संघर्ष करती हैं।
- **अति ऋणग्रस्तता (Overleverage):** उधारकर्ताओं द्वारा पर्याप्त पुनर्भुगतान क्षमता के बिना अत्यधिक ऋण लेने से ऋण चूक हो जाती है।

- **धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार:** ऋण देने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ या भ्रष्टाचार खराब ऋणों का कारण बन सकते हैं।
- **नियामक मुद्दे:** कमजोर नियामक निगरानी के कारण ऋणों का अपर्याप्त जोखिम मूल्यांकन और निगरानी होती है।

प्रभाव

- **आर्थिक मंदी:** बैड लोन(Bad Loans) के उच्च स्तर से ऋण उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे आर्थिक विकास और निवेश धीमा हो जाता है।
- **बैंकों की वित्तीय सेहत:** बैड लोन(Bad Loans) के लिए अधिक प्रावधान के कारण बैंकों को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे लाभप्रदता और स्थिरता प्रभावित होती है।
- **कम ऋण देने की क्षमता:** गैर-निष्पादित ऋणों में अधिक पूंजी लगी होने के कारण, बैंकों के पास उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए कम धन होता है।
- **निवेशकों का विश्वास:** खराब ऋणों के उच्च स्तर से बैंकिंग क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास कम होता है, जिससे शेयर बाजार और विदेशी निवेश प्रभावित होता है।
- **सरकारी भार:** सरकार को वित्तीय दबाव बढ़ाने के लिए बेलआउट या पुनर्पूजीकरण के साथ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **रोजगार की हानि:** बैड लोन(Bad Loans) के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली कंपनियाँ रोजगारों में कटौती कर सकती हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है।

सरकारी पहल

- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC):** संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में तेजी लाने और चूककर्ता उधारकर्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए इसे 2016 में प्रस्तुत किया गया था।
- **बैंकों का पुनर्पूजीकरण:** सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डाली है ताकि उनकी बैलेंस शीट मजबूत हो सके और बैड लोन से निपटने की उनकी क्षमता में सुधार हो सके।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियाँ (ARCs):** बैंकों से बैड लोन खरीदने और मूल्य की वसूली के प्रयास के लिए एआरसी के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया।
- **विवेकपूर्ण मानदंड और तनाव परीक्षण:** ऋण जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए विनियमनों को मजबूत करना और बैंकों का तनाव परीक्षण करना।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन:** कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके अधिक मजबूत एवं अधिक लचीले संस्थान बनाए जाएंगे।
- **ऋण पुनर्गठन:** ऋणदाताओं को चूक को रोकने और पुनर्भुगतान को सुलभ बनाने के लिए कुछ शर्तों के तहत ऋणों का पुनर्गठन करने की अनुमति देना।

निष्कर्ष

- वित्तीय क्षेत्र में बैड लोन एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं, जिसके लिए बैंकों, नियामकों और नीति निर्माताओं के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
- मजबूत ऋण मूल्यांकन, प्रभावी निगरानी एवं कठोर वसूली तंत्र को लागू करके, वित्तीय संस्थाएँ अपने ऋण पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के साथ वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य और लचीलेपन को बनाए रखने के लिए खराब ऋणों की समस्या का समाधान करना आवश्यक होगा।

Source: IE

ब्रिटेन की संसद ने सहायता प्राप्त मृत्यु/असिस्टेड डाइंग (Assisted Dying) को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया

संदर्भ

- ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने के लिए बहुमत से मतदान किया - जो इंग्लैंड और वेल्स में सहायता प्राप्त आत्महत्या का एक कम विवादास्पद पर्याय है।

परिचय

- विधेयक का उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार, मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों को, जिनके पास जीने के लिए छह महीने से भी कम समय बचा है, जीवित रहने की भविष्यवाणी करने का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करना है।
 - ऐसे किसी भी अनुरोध को दो डॉक्टरों और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।
- **वर्तमान कानून:**
 - आत्महत्या (स्वयं द्वारा की गई मृत्यु) या आत्महत्या का प्रयास करना इंग्लैंड और वेल्स में अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं हैं।
 - इसके विपरीत, ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने या आत्महत्या का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता करता है, एक आपराधिक अपराध है जिसके लिए 1961 के सहायक आत्महत्या अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष की जेल की सज़ा है।
- अधिवक्ताओं का मानना है कि नया विधेयक एक मानवीय और दयालु हस्तक्षेप है जो तत्काल परिवार पर दर्दनाक निर्भरता को समाप्त करता है।
- विरोधियों को आशंका है कि गंभीर रूप से विकलांग और कमजोर मरीज़ रिश्तेदारों पर भार कम करने के लिए अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

सहायता प्राप्त मृत्यु/असिस्टेड डाइंग (Assisted Dying) क्या है?

- सहायता प्राप्त मृत्यु से तात्पर्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करने में सहायता करने के कार्य से है, सामान्यतः किसी लाइलाज बीमारी या गंभीर, अनुपचारित दर्द से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए।
- **इसके दो मुख्य रूप हैं:**
 - **सहायता प्राप्त/असिस्टेड आत्महत्या:** एक व्यक्ति, किसी चिकित्सा पेशेवर या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से, सामान्यतः दवा की निर्धारित घातक खुराक का सेवन करके, अपना जीवन समाप्त कर लेता है।
 - **इच्छामृत्यु:** एक डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, अत्यधिक पीड़ा से राहत देने के लिए, सामान्यतः रोगी के अनुरोध पर, उसके जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से एक घातक पदार्थ का प्रशासन करता है।
- सहायता प्राप्त मृत्यु का अभ्यास अत्यधिक विवादास्पद है और केवल कुछ देशों या क्षेत्रों में ही वैध है, जहाँ इसे अनुमति दी गई है वहाँ कठोर दिशा-निर्देश एवं नियम हैं।
 - स्विट्जरलैंड पहला देश था जिसने 1942 में सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाया। बाद में यू.एस., ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संबंधित कानून बनाए।
 - कनाडा के 2016 के चिकित्सा सहायता कानून का लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं जिनकी हालत गंभीर नहीं है।

भारत की स्थिति क्या है?

- उच्चतम न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया था, जो व्यक्ति के पास "लिविंग विल" होने पर निर्भर करता है।
 - उच्चतम न्यायालय ने माना कि 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
 - लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज है जो यह निर्दिष्ट करता है कि यदि व्यक्ति भविष्य में अपने स्वयं के चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए।
 - गोवा पहला राज्य है जिसने कुछ सीमा तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप दिया है।
- हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिए चिकित्सा सहायता वापस लेने के बारे में मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए।
 - इनमें स्पष्ट किया गया है कि डॉक्टरों को जीवन-रक्षक उपाय प्रारंभ करने से बचना चाहिए, जब वे रोगी को कोई लाभ नहीं पहुँचाते हैं और इससे रोगी को पीड़ा एवं सम्मान की हानि होने की संभावना होती है।

सहायता प्राप्त मृत्यु के पक्ष में तर्क

- **स्वायत्तता और विकल्प:** व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें लंबे समय तक पीड़ा से बचने के लिए इसे समाप्त करने का विकल्प भी शामिल है।
- **पीड़ा से राहत:** सहायता प्राप्त मृत्यु उन लोगों के लिए एक दयालु विकल्प प्रदान करती है जो घातक बीमारियों या असहनीय दर्द से पीड़ित हैं, जिससे उन्हें सम्मान के साथ मरने की अनुमति मिलती है।
- **जीवन की गुणवत्ता:** कुछ लोगों के लिए, जीवन की गुणवत्ता उस बिंदु तक खराब हो सकती है जहाँ मृत्यु को निरंतर पीड़ा या स्वतंत्रता की हानि के साथ जीने से बेहतर विकल्प माना जाता है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान:** लोगों को अपने शरीर एवं जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें मानवीय और नियंत्रित तरीके से अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय भी सम्मिलित है।

सहायता प्राप्त मृत्यु के विरुद्ध तर्क

- **नैतिक और नीतिपरक चिंताएँ:** विभिन्न लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति के अनुरोध पर भी, किसी की जान लेना नैतिक रूप से गलत है और जीवन की पवित्रता के विरुद्ध है।
- **दुरुपयोग का जोखिम:** कमजोर व्यक्ति, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या परिवार के दबाव वाले व्यक्ति, सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प चुनने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
- **चिकित्सा नैतिकता:** स्वास्थ्य सेवा पेशेवर पारंपरिक रूप से जीवन को बचाने के लिए बाध्य हैं, और सहायता प्राप्त मृत्यु उपचार एवं देखभाल में डॉक्टरों की मौलिक भूमिका के साथ संघर्ष कर सकती है।
- **वैकल्पिक समाधान:** अधिवक्ताओं का तर्क है कि उपशामक देखभाल और दर्द प्रबंधन राहत प्रदान कर सकता है, जिससे सहायता प्राप्त मृत्यु अनावश्यक हो जाती है।

आगे की राह

- **मजबूत विनियमन:** यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त विधिक सुरक्षा उपायों को लागू करना कि यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
- **उपशामक देखभाल विस्तार:** पीड़ा को दूर करने और सहायता प्राप्त मृत्यु की माँग को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली उपशामक देखभाल तक पहुँच में सुधार करना।
- **सार्वजनिक परिचर्चा:** सहायता प्राप्त मृत्यु के नैतिक, विधिक और नैतिक निहितार्थों के बारे में चल रही चर्चाओं पर दिशा-निर्देश तैयार करते समय विचार किया जा सकता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:** प्रभावी विनियमन और सुरक्षा उपायों पर मार्गदर्शन के लिए देश विधिक सहायता प्राप्त मृत्यु ढाँचे वाले देशों (जैसे, नीदरलैंड, कनाडा) की ओर देख सकते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** जबरदस्ती या आवेगपूर्ण निर्णयों को रोकने और सूचित सहमति सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करना।

Source: TH

वैश्विक पोलियो पुनरुत्थान और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि इस वर्ष सितम्बर से अब तक पाँच देशों - फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में अपशिष्ट जल प्रणालियों की नियमित निगरानी के दौरान पोलियोवायरस का पता लगाया गया है।

पोलियो क्या है?

- पोलियो (पोलियोमाइलाइटिस) पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है।
- यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और इससे लकवा, विकलांगता या यहाँ तक कि मृत्यु जैसी गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं।
- **प्रसार:** पोलियो मुख्य रूप से फेकल-ओरल ट्रांसमिशन के माध्यम से प्रसारित होता है।
 - यह खाँसने या छींकने से निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से भी प्रसारित हो सकता है।
- **लक्षण:** अधिकांश मामले हल्के या बिना लक्षण वाले होते हैं।
 - संक्रमित व्यक्तियों का एक छोटा प्रतिशत लकवाग्रस्त पोलियो विकसित करता है, जो लकवा का कारण बन सकता है, जो सामान्यतः पैरों या श्वसन मांसपेशियों को प्रभावित करता है।
- **टीकाकरण:** पोलियो का कोई उपचार नहीं है, इसे केवल रोका जा सकता है।
 - कई बार दिया जाने वाला पोलियो का टीका एक बच्चे को जीवन भर के लिए सुरक्षित कर सकता है।
- **उपलब्ध टीके:** मौखिक पोलियो टीका और निष्क्रिय पोलियो टीका। दोनों प्रभावी और सुरक्षित हैं।
 - जंगली पोलियोवायरस(WPV) तीन प्रकार के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3।

पोलियो उन्मूलन की स्थिति

- **उन्मूलन:** सितंबर 2015 में टाइप 2 जंगली पोलियोवायरस(wild poliovirus) को समाप्त घोषित किया गया और अक्टूबर 2019 में टाइप 3 जंगली पोलियोवायरस(wild poliovirus) को समाप्त घोषित किया गया।
 - केवल टाइप 1 जंगली पोलियोवायरस(wild poliovirus) बचा है।
- WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को 2014 में पोलियोवायरस से मुक्त घोषित किया गया था और WHO अफ्रीकी क्षेत्र को 2020 में जंगली पोलियोवायरस(wild poliovirus) से मुक्त प्रमाणित किया गया था।
 - भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था और यह अभी भी जारी है।
- WHO के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान विश्व के एकमात्र ऐसे देश हैं जहाँ पोलियो स्थानिक बना हुआ है।

पोलियो उन्मूलन के लिए टीके

- **ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV):** एक जीवित-क्षीणित वैक्सीन जिसका उपयोग इसके प्रशासन में आसानी और म्यूकोसल प्रतिरक्षा प्रेरण के लिए किया जाता है।
 - हालाँकि, यह वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) और निरंतर संचरण का कारण बन सकता है।
- **निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन (IPV):** एक गैर-जीवित वैक्सीन जो बीमारी या संचरण का कारण बने बिना सभी तीन प्रकार के पोलियोवायरस से सुरक्षा प्रदान करती है।
 - शोधकर्ता तेजी से उन्मूलन के लिए OPV-टू-IPV स्विच का समर्थन करते हैं।

पोलियो उन्मूलन में वैश्विक प्रयास

- **वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI):** इसका लक्ष्य सभी जंगली, वैक्सीन-संबंधी और सबिन पोलियोवायरस का उन्मूलन एवं रोकथाम करना है, ताकि कोई भी बच्चा फिर कभी लकवाग्रस्त पोलियोमाइलाइटिस से पीड़ित न हो।
 - GPEI के चार स्तंभों में नियमित टीकाकरण, पूरक टीकाकरण, निगरानी और लक्षित सफाई अभियान शामिल हैं।
 - बर्लिन, जर्मनी में 2022 के विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में, वैश्विक नेताओं ने पोलियो को समाप्त करने के लिए GPEI को \$2.6 बिलियन देने का वचन दिया।
- वैश्विक पोलियो उन्मूलन रणनीति 2022-2026 पोलियो मुक्त विश्व को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है, जो GPEI हितधारकों, भागीदारों, दाताओं और प्रभावित सरकारों के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है।
- विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो जोनास साल्क की जन्म तिथि है, जिन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के विरुद्ध टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था।

पोलियो उन्मूलन में भारत के प्रयास

- **पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत (1995):** इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) रणनीति का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत 1 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुँचा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि पाँच वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को टीका लगाया जाए।
 - यह अभियान "दो बूँद ज़िंदगी की" नारे के साथ मशहूर हो गया।
 - पल्स पोलियो अभियान भी घर-घर जाकर किए जाने वाले प्रयासों पर काफ़ी सीमा तक निर्भर था, ताकि पहुँच से दूर के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक पहुँचा जा सके।
- **नियमित टीकाकरण और प्रणाली सुदृढीकरण:** UIP ने पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खाँसी), टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी और तपेदिक के विरुद्ध मुफ्त टीके उपलब्ध कराए।
- **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV) परिचय (2015):** IPV पोलियो के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से टाइप 2 पोलियोवायरस के विरुद्ध।

आगे की राह

- वैश्विक स्तर पर नियमित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अपशिष्ट जल में पोलियो वायरस की रिपोर्ट करने वाले देशों में।
- सभी बच्चों, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में, टीकाकरण सुनिश्चित करके टीकाकरण असमानताओं को दूर करें।
- टीका-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) के जोखिम को खत्म करने के लिए धीरे-धीरे OPV से IPV में परिवर्तन करें।

निष्कर्ष

- जब तक एक भी बच्चा संक्रमित रहता है, सभी देशों के बच्चों को पोलियो होने का जोखिम बना रहता है।
- इन अंतिम बचे गढ़ों से पोलियो को समाप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप रोग का वैश्विक पुनरुत्थान हो सकता है।

Source: TH

भारत का समुद्री क्षेत्र

संदर्भ

- जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, इसका समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में उभर रहा है।

भारत के समुद्री क्षेत्र का परिचय

- भारत की समुद्री विरासत इसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा जितनी ही विशाल एवं गतिशील है, जिस पर 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह स्थित हैं, जो सामूहिक रूप से इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।
- यह देश के व्यापार का लगभग 95% मात्रा और 70% मूल्य के साथ प्रबंधन करता है।
- 2023 में, देश ने वैश्विक विकास में 16% का योगदान दिया, और कुछ अनुमानों के अनुसार, यह आगामी तीन वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

सामरिक महत्त्व

- प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्त्व को रेखांकित करती है।
- पूर्वी एशिया और अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका जैसे गंतव्यों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश मालवाहक जहाज भारतीय जल से होकर गुजरते हैं।
- यह न केवल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक समुद्री शासन को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

New Frontiers

- Focuses on connectivity, infrastructure, and development in a rapidly evolving global landscape.

Blue Growth

- Emphasizes building partnerships to advance progress in maritime trade and commerce.

Green and Blue

- Highlights sustainability, technology, and innovation as critical factors for a greener maritime future

Coasts and Communities

- Explores maritime governance and its social impact, centering on coastal communities and sustainable development.

प्रमुख पहल और विकास

- **सागरमंथन 2024:** इसका आयोजन पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से किया गया था, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच है।
 - यह नीली अर्थव्यवस्था, वैश्विक आपूर्ति शृंखला, समुद्री रसद और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है।
- **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030:** इसमें भारत को वैश्विक समुद्री नेतृत्व के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 150 पहलों की रूपरेखा दी गई है।
 - इसमें बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों के विकास को शामिल किया गया है, जिसमें स्थिरता एवं नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख पहलों में ग्रीन एवं स्मार्ट पोर्ट; बेड़े का विस्तार; और बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।
- **पंच कर्म संकल्प:** इसमें भारत में ग्रीन शिपिंग और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली पाँच प्रमुख घोषणाएँ शामिल हैं।
 - MoPSW का लक्ष्य ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिसमें ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम और ग्रीन हाइड्रोजन हब आदि शामिल हैं।
- **सागरमाला कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य पूरे भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय विकास और कनेक्टिविटी संवर्द्धन का समर्थन करता है।
 - तटीय घाट, सड़क और रेल संपर्क, मछली बंदरगाह, कौशल विकास, कूज टर्मिनल एवं रो-पैक्स नौका सेवाओं जैसी परियोजनाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत के समुद्री क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ और अवसर

- **बुनियादी ढाँचा और आधुनिकीकरण:** भारत का लक्ष्य 2047 तक शीर्ष पाँच समुद्री देशों में से एक बनना है, जिसके लिए बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।
 - 1,600 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मिलियन मीट्रिक टन करने की आवश्यकता है।
 - इसके लिए बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, कार्गो हैंडलिंग सिस्टम को बेहतर बनाना और हरित बंदरगाहों एवं शिपिंग को विकसित करना आवश्यक है।
- **नियामक और नीतिगत ढाँचा:** आगामी तटीय शिपिंग विधेयक एवं मर्चेन्ट शिपिंग विधेयक से तटीय शिपिंग को बढ़ावा मिलने और व्यावसायिक संचालन को आसान बनाने की संभावना है।
 - हालाँकि, इन कानूनों को उनके इच्छित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और नियामक स्पष्टता महत्वपूर्ण है।
- **सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियाँ:** स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का चालू होना और समुद्री डकैती विरोधी उपायों का विकास समुद्री स्थिरता पर भारत के ध्यान को उजागर करता है।
 - हालाँकि, इन क्षमताओं को बनाए रखना और उन्नत करना एक सतत चुनौती होगी।
- **आर्थिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक नेता बनने के लिए, भारत को अपने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार करना होगा, कंटेनर के ठहरने के समय को कम करना होगा और टर्नअराउंड समय को बढ़ाना होगा।
 - इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होंगे।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** समुद्री क्षेत्र को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करना चाहिए।

- ग्रीन पोर्ट एवं ग्रीन शिपिंग जैसी पहल आवश्यक हैं, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है।
- भारतीय तटरक्षक बल समुद्री पर्यावरण संरक्षण और तेल रिसाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **मानव संसाधन और कौशल विकास:** इसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग कौशल विकास और ज्ञान हस्तांतरण में सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष

- भारत का समुद्री क्षेत्र रणनीतिक पहलों और सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है।
- सागरमाला कार्यक्रम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं तथा बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार कर रहे हैं।
- सागरमंथन से मिली जानकारी के साथ ये प्रयास भारत के समुद्री क्षेत्र को एक सतत और अभिनव भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी भूमिका स्थापित होती है।

Source: PIB

AI स्कूल में सीखने के परिणामों को बेहतर बना सकता है

संदर्भ

- भारत की शिक्षा प्रणाली में छात्रों की कम भागीदारी के कारण सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए जनरेटिव AI जैसे नवीन समाधानों की आवश्यकता है।

शिक्षा प्रणाली में AI प्रौद्योगिकियाँ

- **अनुकूली शिक्षण प्रणालियाँ:** व्यक्तिगत छात्र की आवश्यकताओं और प्रगति के आधार पर सीखने की सामग्री एवं कठिनाई को समायोजित करें।
- **बुद्धिमान ट्यूटोरिंग सिस्टम (ITS)** एक-से-एक मार्गदर्शन और इंटरैक्टिव पाठ प्रदान करते हैं।
- AI-संचालित चैटबॉट संदेहों को हल करने और संसाधन प्रदान करने के लिए आभासी सहायक के रूप में कार्य करते हैं।
- **स्वचालित ग्रेडिंग सिस्टम:** वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक मूल्यांकन दोनों के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं को स्वचालित करें।
- AI सुविधाओं वाले वर्चुअल क्लासरूम इंटरैक्टिव AI टूल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाते हैं।

शिक्षा में AI के लाभ

- **समावेशी शिक्षा के लिए सहायता:** AI उपकरण टेक्स्ट-टू-स्पीच, वॉयस कमांड और रीयल-टाइम अनुवाद जैसी सुविधाओं के माध्यम से विकलांग छात्रों की सहायता कर सकते हैं।
- **रीयल-टाइम फीडबैक:** त्वरित फीडबैक तंत्र छात्रों को गलतियों को पहचानने और उन्हें तुरंत सुधारने में सहायता करता है, जिससे निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलता है।
- **व्यक्तिगत शिक्षण:** AI प्रत्येक शिक्षार्थी की गति और शैली को अनुकूलित करता है, जिससे समझ बढ़ती है।

- **पहुंच:** दूरदराज के क्षेत्रों को AI-संचालित प्लेटफॉर्म से लाभ होता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है।

शिक्षा में AI की चुनौतियाँ

- **AI सिस्टम में पूर्वाग्रह:** त्रुटिपूर्ण या पक्षपाती डेटासेट पर प्रशिक्षित AI उपकरण असमानताओं को बनाए रख सकते हैं, जिससे अनुचित या भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता:** AI उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता आलोचनात्मक सोच एवं स्वतंत्र सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे छात्र सूचना के निष्क्रिय उपभोक्ता बन सकते हैं।
- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** यदि नैतिक और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो संवेदनशील छात्र डेटा का संग्रह और उपयोग महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करता है।
- **डिजिटल डिवाइड:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के पास AI उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच की कमी है।

सरकारी कदम

- **युवाओं के लिए जिम्मेदार AI 2022:** यह कार्यक्रम छात्रों को AI कौशल प्राप्त करने और कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने के अवसर प्रदान करता है।
- **युवाई(YUVAi):** AI के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि छात्रों को AI तकनीक सीखने एवं सामाजिक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** शिक्षा के सभी स्तरों पर AI सहित समकालीन विषयों को पेश करने के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।

आगे की राह

- **नैतिक डिजाइन:** AI उपकरण निष्पक्ष डेटासेट पर बनाए जाने चाहिए और भेदभावपूर्ण परिणामों को रोकने के लिए नियमित रूप से ऑडिट किए जाने चाहिए।
- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** छात्र की जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा कानून और रूपरेखा लागू की जानी चाहिए।
- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** शिक्षकों को AI उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और छात्रों को जिम्मेदारी से उनका उपयोग करने में मार्गदर्शन करने के कौशल से युक्त होना चाहिए।
- **संतुलित एकीकरण:** AI को पारंपरिक शिक्षण विधियों का पूरक होना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना चाहिए, ताकि समग्र शिक्षण अनुभव सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

- AI में सीखने को अधिक व्यक्तिगत, आकर्षक और सुलभ बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन करने की अपार क्षमता है।
- उचित सुरक्षा उपायों के साथ, AI महत्वपूर्ण विचारकों, नवप्रवर्तकों और आजीवन सीखने वालों की एक पीढ़ी को प्रोत्साहित कर सकता है, जो भारत को एक उज्ज्वल शैक्षिक भविष्य की ओर ले जाएगा।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

मलेरिया उन्मूलन में भारत की प्रगति

समाचार में

स्वतंत्रता के समय मलेरिया के वार्षिक मामलों की संख्या 7.5 करोड़ से घटकर 2023 तक 20 लाख हो जाएगी, अर्थात् 97 प्रतिशत से अधिक की कमी

मलेरिया

- यह एक जानलेवा बीमारी है जो विशेष प्रकार के मच्छरों से प्रसारित होती है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय देशों में।
- **संचरण:** अधिकांशतः संक्रमित मादा एनोफ़ेलीज़ मच्छरों के काटने से।
 - रक्त आधान और दूषित सुई भी मलेरिया प्रसारित कर सकती है।
- इसे रोका जा सकता है और इसका उपचार किया जा सकता है।
- संक्रमण एक परजीवी के कारण होता है, व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

- WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 भारत की प्रगति को सराहा गया है।
 - भारत 2024 में WHO के उच्च भार से उच्च प्रभाव (HBHI) समूह से बाहर निकल गया।
 - 2017 और 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मृत्युओं में भारी गिरावट आई।
- विभिन्न राज्य 2015 से 2023 तक कम रोग भार श्रेणियों में चले गए।
 - 2023 तक केवल दो राज्य (मिजोरम और त्रिपुरा) उच्च भार श्रेणी में रह गए हैं।

व्यापक रणनीति:

- मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (NFME) 2016 में प्रारंभ की गई।
- मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023-2027) ने बेहतर निगरानी और वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग की शुरुआत की।
- **एकीकृत वेक्टर प्रबंधन (IVM):** मच्छरों की जनसंख्या को कम करने के लिए इनडोर अवशिष्ट छिड़काव (IRS) और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (LLIN) का उपयोग किया जाता है।
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पैकेज में मलेरिया की रोकथाम और उपचार शामिल है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है।
 - 2027 तक शून्य स्वदेशी मामले प्राप्त करने और मलेरिया को फिर से स्थापित होने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

Source :TH

डॉ. मनमोहन सिंह का योगदान

संदर्भ

- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

डॉ. मनमोहन सिंह का परिचय

- इनका जन्म 26 सितंबर, 1932 को अविभाजित पंजाब, भारत में हुआ था।
- उन्होंने लगातार दो कार्यकाल 2004-09 और 2009-14 तक देश के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।

प्रमुख योगदान

- **सरकारी सेवा:** 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए।
 - 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए।
 - वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
- **आर्थिक सुधार:** 1990 के दशक में वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने, व्यापार बाधाओं को कम करने, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण करने और तेजी से विकास को बढ़ावा देने वाले सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **भारत की GDP वृद्धि:** भारत ने मजबूत आर्थिक विकास का अनुभव किया, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था औसतन 7-8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी।
- **राजकोषीय और बैंकिंग सुधार:** उन्होंने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और मुद्रास्फीति को संबोधित करने में योगदान दिया।
- **परमाणु सौदा (2008):** उन्होंने ऐतिहासिक US-भारत असैन्य परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया और परमाणु प्रौद्योगिकी एवं ईंधन तक पहुँच सुनिश्चित की।
- **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम:** उनकी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) और सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) सहित प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किए।
- **साहित्यिक कार्य:** उन्होंने भारत की आवक-उन्मुख व्यापार नीति की आलोचना करते हुए "भारत के निर्यात रुझान और स्व-संधारणीय विकास की संभावनाएँ" (1964) नामक पुस्तक भी लिखी।
- **पुरस्कार और सम्मान:** भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण (1987) से सम्मानित।
 - वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड और यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित (1993, 1994)।
 - एडम स्मिथ पुरस्कार (1956) और राइट पुरस्कार (1955) से सम्मानित।

Source: TH

बाल्ड ईगल(Bald Eagle)

संदर्भ

- बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है।

परिचय

- बाल्ड ईगल उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है।
- **स्वरूप:** बाल्ड ईगल का सिर और पूँछ सफ़ेद रंग की होती है, जबकि शरीर एवं पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी पीली चोंच बड़ी एवं हुकदार होती है, और इसके पंजे शक्तिशाली होते हैं।



- **आहार:** वे माँसाहारी पक्षी हैं, जो मुख्य रूप से मछली खाते हैं, लेकिन जलपक्षी का शिकार भी करते हैं या सड़े हुए माँस को भी खाते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट सील एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसका उपयोग 1782 से संधियों और आयोगों जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है।
- **प्रतीकात्मकता:** बाल्ड ईगल शक्ति, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक है।
- **वितरण:** यह कनाडा, USA, मैक्सिको एवं सेंट पियरे और मिकेलॉन के फ्राँसीसी द्वीप क्षेत्रों में प्रजनन करता है
- **संरक्षण:** बाल्ड ईगल को 1940 के राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के तहत भी संरक्षित किया गया है, जो प्राणी को बेचना या शिकार करना अवैध बनाता है।
 - **IUCN रेड लिस्ट की स्थिति:** इसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

Source: IT

वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक सक्षमीकरण के लिए समिति

समाचार में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में उत्तरदायी और नैतिक AI उपयोग के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसे FREE-AI नाम दिया गया है।

समिति के बारे में

- समिति का नेतृत्व IIT बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे।
- **समिति के उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर और भारत में वित्तीय सेवाओं में AI को अपनाने की वर्तमान स्थिति का आकलन करना।
 - वित्तीय क्षेत्र में AI पर वैश्विक विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करना।
 - AI से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करना और वित्तीय संस्थानों (बैंक, NBFCs, फिनटेक, PSOs, आदि) के लिए शमन, मूल्यांकन एवं निगरानी ढाँचे की सिफारिश करना।
 - भारतीय वित्तीय क्षेत्र में शासन संबंधी पहलुओं सहित उत्तरदायी और नैतिक AI अपनाने के लिए एक ढाँचे की सिफारिश करना।
 - भारतीय वित्तीय क्षेत्र के अंदर AI से संबंधित किसी भी अन्य मामले को संबोधित करना।
- **समयरेखा:** समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Source:TH

चीन विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध बनाएगा

संदर्भ

- चीन ने भारतीय सीमा के निकट विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बाँध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे तटवर्ती देशों - भारत और बांग्लादेश में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

बाँध के बारे में

- इसका निर्माण हिमालय क्षेत्र में एक विशाल घाटी में किया जाएगा, जहाँ यारलुंग जांग्बो नदी (ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम) अरुणाचल प्रदेश (भारत) और फिर बांग्लादेश में बहने से पहले एक तीव्र मोड़ लेती है।



- एक ट्रिलियन युआन (\$137 बिलियन) से अधिक की लागत वाली इस परियोजना से वार्षिक 300 बिलियन kWh से अधिक बिजली उत्पन्न होने की संभावना है, जो 300 मिलियन से अधिक लोगों की वार्षिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
 - यह क्षमता मध्य चीन में श्री गॉर्ज डैम की 88.2 बिलियन kWh से काफी अधिक होगी, जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।
- यह परियोजना 2020 में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के एक प्रमुख नीति निकाय प्लेनम द्वारा अपनाई गई 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) और राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास और वर्ष 2035 तक दीर्घकालिक उद्देश्यों का भाग है।
- हालाँकि, बाँध भी भारी इंजीनियरिंग चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह स्थल भूकंप के प्रति संवेदनशील टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है।

भारत और बांग्लादेश की चिंताएँ:

- बाँध के निर्माण से चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार मिल सकता है, जिससे संघर्ष के समय में संभावित रूप से बड़ी मात्रा में जल निकाला जा सकता है।
 - भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर अपना बाँध बना रहा है।
- नदी के प्रवाह और क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर बाँध के प्रभाव के बारे में भारत और बांग्लादेश ने चिंता व्यक्त की है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ELM) की स्थापना की, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी एवं सतलुज नदी पर जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

Source: IE

सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती

संदर्भ

- 26 दिसंबर को भारत ने साहस, न्याय और अटूट दृढ़ संकल्प के प्रतीक उधम सिंह की 125वीं जयंती मनाई।

परिचय

- उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर, 1899 को पंजाब के सुनाम में शेर सिंह के रूप में हुआ था। वे एक भावुक देशभक्त और दृढ़ निश्चय के प्रतीक थे।

- वे ग़दर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़े एक भारतीय क्रांतिकारी थे।

जनरल ओ'डायर की हत्या

- सरदार उधम सिंह को 1940 में अविभाजित भारत के पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ'डायर की हत्या के लिए जाना जाता है।
- यह हत्या 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी।
- जनरल ओ'डायर उस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें सिंह स्वयं बच गए थे।

परीक्षण और निष्पादन

- उधम सिंह पर लंदन में मुकदमा चलाया गया। हिरासत में रहते हुए उन्होंने भारत के तीन प्रमुख धर्मों और अपनी उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना नाम 'राम मोहम्मद सिंह आज़ाद' उपयोग किया।
- 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।

Source: THEWEEK

ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में "ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) विधेयक, 2024" पारित किया।
 - यह विधेयक कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने का दायित्व डालता है।

सोशल मीडिया का प्रभाव

- सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक तुलना, छूट जाने का डर (FOMO) और साइबरबुलिंग के कारण अकेलेपन, अवसाद और चिंता की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।
- सोशल मीडिया पर सामग्री की त्वरित, तेज़ गति वाली प्रकृति ध्यान अवधि को कम करती है, जिससे उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है जिनमें गहन ध्यान की आवश्यकता होती है।

वैश्विक परिदृश्य

- चीन ने 2023 में "मोबाइल इंटरनेट के लिए नाबालिगों के लिए मोड की स्थापना के लिए दिशानिर्देश" का मसौदा जारी किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1998 में पारित बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA) के अनुसार, "वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं के संचालकों" को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के व्यक्तिगत विवरण तक पहुँचने के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त, माता-पिता की सहमति लेने की आवश्यकता होती है।
- 2023 में, फ्रांस ने एक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत सामाजिक नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तब तक पहुँच से मना करना होगा जब तक कि वे माता-पिता या अभिभावक द्वारा अधिकृत न हों।

भारतीय परिदृश्य

- भारत में अभी तक 13 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकता है।
 - सोशल मीडिया पर वे कितना समय बिता सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2023 में मनोरंजन उद्योग में बच्चों और किशोरों की भागीदारी के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Source: TH

